**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2060**

**सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2014 को उत्‍तर देने हेतु**

**राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा संस्‍थान की स्‍थापना**

**2060. डॉ चंदन मित्रा : क्‍या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या सरकार एक राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा के संस्‍थान की स्‍थापना किए जाने का विचार रखती है;
2. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरे सहित उक्‍त संस्‍थान के विचारार्थ विषय, उद्देश्‍य एवं लक्ष्‍य क्‍या-क्‍या हैं ; और
3. सरकार द्वारा विशेष रुप से मध्‍य प्रदेश में अधिकतम लागत लाभ सुनिश्चित करने हेतु सौर ऊर्जा संबंधी नवीनतम प्रौद्योगिकियों के प्रवर्तन की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने तथा उसमें तेजी लाने और उसका शीघ्र वाणिज्यिककरण करने के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए हैं?

उत्‍तर

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

 **(श्री पीयूष गोयल)**

1. और (ख) : सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ‘’राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा संस्‍थान(नाईस)’’ नामक एक स्‍वायत्‍त संस्‍थान की स्‍थापना की है जो मौजूदा सौर ऊर्जा केंद्र को परिवर्तित कर इसके मुख्‍यालय तथा अनुसंधान सुविधाओं सहित ग्‍वाल पहाड़ी गांव जिला गुड़गांव (हरियाणा) में स्‍थापित है। ‘नाईस’ को हरियाणा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है ।

 इस राष्‍ट्रीय संस्‍थान की स्‍थापना का उद्देश्‍य तकनीकी मुद्दों पर मंत्रालय की सहायता करना तथा अनुसंधान व प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित प्रमुख राष्‍ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करना है । इसे निम्‍नलिखित कार्य सौंपे हैं:-

1. सौर तापीय तथा सौर प्रकाशवोल्‍टीय प्रणाली में अनुसंधान और विकास
2. संसाधन मूल्‍यांकन
3. परीक्षण व मानकीकरण
4. सहयोग, निगरानी तथा परामर्श तथा
5. प्रशिक्षण

इसके कार्यों का प्रबंधन सचिव, एमएनआरई की अध्‍यक्षता में एक शासी परिषद तथा महानिदेशक की अध्‍यक्षता में एक कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है ।

सरकार आगामी दस वर्षों तक संस्‍थान के योजना, गैर-योजना और पूंजीगत व्‍यय के लिए बजटीय सहायता अथवा अनुदान प्रदान करेगी । इसे धीरे-धीरे आत्‍मनिर्भर बनना है ।

(ग) नवीनतम सौर प्रौद्योगिकियों के प्रवर्तन की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने और इसमें तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्‍नानुसार हैं :

(i) भारत सरकार ने 11 जनवरी, 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) का शुभारंभ किया है । इस मिशन का लक्ष्‍य वर्ष 2022 तक तीन चरणों में 20,000 मेगावाट क्षमता ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत की संस्‍थापना करना है ।

(ii) ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों पर सब्‍सिडी का अनुदान

(iii) राष्‍ट्रीय सीमा शुल्‍क नीति में सौर विद्युत के लिए अक्षय ऊर्जा खरीद की बाध्‍यता का प्रावधान किया गया है ।

(iv) सौर विद्युत संयंत्रों की स्‍थापना के लिए रियायती आयात शुल्‍क/उत्‍पाद शुल्‍क, वर्धित मूल्‍यह्रास तथा करावकाश ।

(v) ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए विभिन्‍न मध्‍यस्‍थताओं के माध्‍यम से समय- समय पर मिश्रित विद्युत हेतु उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन तथा सुविधा की घोषणा की जाती है।

1. जागरूकता संबंधी कार्यक्रम जैसे प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यशालाएं आदि आयोजित की जा रही हैं।
2. नई प्रौद्योगिकियों तथा कार्य क्षमता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी कई प्रयासों की पहल की गई ।

निजी सौर विद्युत विकासकर्त्‍ता अपनी वित्‍तीय स्‍थिति और अन्‍य संबंधित कारकों के अनुसार प्रौद्योगिकी का चयन करने के लिए स्‍वतंत्र हैं ।

......